

बढ़ेगी चीनी शेयरों की मिठास

उज्ज्वल जौहरी

न कसान का दबाव झेल रहे चीनी उद्योग को वित्तीय पैकेज और पेट्रोल में 10 फीसदी तक एथेनॉल मिश्रण के सुझाव से कुछ राहत मिली है। हालांकि चीनी कंपनियों को इसका वास्तविक रूप से फायदा तभी मिलेगा जब गन्ना कीमतों से संबद्ध समिति अपनी सिफारिशें पेश करेगी। विश्लेषकों का कहना है कि चीनी उत्पादकों के लिए लाभ एक साल के बाद ही मिलना शुरू होगा। वित्तीय प्रदर्शन, बिजनेस मॉडल और चीनी कंपनियों के कर्ज स्तरों को देखते हुए विश्लेषक मध्यावधि परिदृश्य से बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका शुगर्स को पसंद कर रहे हैं।

नकदी किल्लत का सामना कर रहे चीनी उद्योग पर उत्तर प्रदेश (भारत के चीनी उत्पादन में एक-तिहाई से अधिक योगदान) में चीनी वर्ष 2012-13 से 2400 करोड़ रुपये के गन्ने का बकाया था। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की कीमत चीनी वर्ष 2013-14 के लिए चीनी वर्ष 2012-13 के 280 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बनाए रखी है और मार्च-अप्रैल में गन्ने का बकाया 12,000-13,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाने का अनुमान है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा चीनी उद्योग को बकाया के भुगतान के संदर्भ में 7200 करोड़ रुपये का ऋण (12 फीसदी की ब्याज रियायत के साथ, 7 फीसदी की रियायत चीनी विकास फंड और 5 फीसदी का भुगतान सरकार द्वारा) मुहैया कराए जाने का निर्णय शुभ संकेत है। इससे उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों में गन्ने की पेराई के लिए उत्साह बढ़ा है, जिसमें लगभग एक महीने तक का विलंब हो चुका है। उद्योग को ऋण के भुगतान पर दो वर्षों की छूट भी मुहैया कराई जाएगी। सरकार मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन पर भी ध्यान दे रही है जिससे उद्योग के 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को देखते हुए कुछ राहत मिलनी चाहिए।

हालांकि यह सब सकारात्मक है और इससे चीनी मिलों को उत्तर प्रदेश में उत्पादन शुरू करने एवं किसानों को बकाया मिलने में मदद मिलेगी, लेकिन मुनाफे से जुड़ी प्रमुख समस्या को दूर किया जाना अभी भी बाकी है। इस पर गौर करें कि उद्योग 225 रुपये प्रति क्विंटल की गन्ना खरीद कीमत की मांग कर रहा था जो मौजूदा चीनी कीमतों को देखते हुए उचित है। लेकिन उत्तर प्रदेश



में चीनी उत्पादकों को अभी भी 270 रुपये की गन्ना खरीद कीमत (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 11 रुपये के डिस्काउंट के बाद) चुकानी होगी। लगभग 9 फीसदी की रिकवरी दर को देखते हुए प्रति किलोग्राम चीनी उत्पादन के लिए कच्चे माल की लागत 30 रुपये आएगी। लगभग 34 रुपये प्रति किलोग्राम की कन्वर्जन लागत को शामिल करें तो चीनी उत्पादन की लागत 30.34 रुपये प्रति किलोग्राम (30-31 रुपये प्रति किलोग्राम की बिक्री कीमत के समान) बैठेगी। ब्याज और मूल्यहास जैसी अन्य लागत को देखते हुए चीनी कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बना रहेगा।

पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण को 5 फीसदी से दोगुना बढ़ा कर 10 फीसदी करने से भी फायदा होगा। 10 फीसदी एथेनॉल मिश्रण के लिए अधिक शीरे की जरूरत होगी, अन्यथा इस शीरे का इस्तेमाल चीनी बनाने में किया जाता। इसके परिणामस्वरूप चीनी उत्पादन में कमी से कीमतों में इजाफा हो सकता है। जेएम फाइनैशियल के अचल लोहाड़े का मानना है कि इस पहल से सालाना चीनी उत्पादन में 10-20 लाख टन की कमी आ सकती है और भारत के अधिशेष चीनी भंडार पर दबाव पड़ सकता है। इस्मा के महानिदेशक अभिनाश वर्मा का भी मानना है कि 10 फीसदी के एथेनॉल मिश्रण से 17-17 लाख टन अधिशेष चीनी उत्पादन में कमी आ सकती है।

उत्पादकों के लिए परिदृश्य

विभिन्न तथ्यों को देखते हुए चीनी शेयरों पर कुछ दबाव दिखा है। इनमें बलरामपुर चीनी का परिदृश्य अच्छा दिख रहा है।

चीनी उद्योग को भविष्य में राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं

डिस्टिलरी क्षमताओं की वजह से यह अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों से काफी हद तक अलग है। श्री रेणुका शुगर्स भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि उसे कर्नाटक (जहां मूल्य निर्धारण का कारक चीनी कंपनियों से जुड़ा हुआ है) में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि महाराष्ट्र (जहां चीनी मूल्य निर्धारण व्यवस्था पर समिति गठित की गई है) में लाभ अगले साल ही मिलेगा।

एसपीए सिक्क्योरिटीज के रोहित अग्रवाल का कहना है कि 1.01 करोड़ टन का अंतरराष्ट्रीय चीनी अधिशेष भंडार घट कर 35 लाख टन रह जाने का अनुमान है जिससे श्री रेणुका को अपने ब्राजीलियाई परिचालन में में फायदा मिलेगा। अधिशेष में कमी से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें मजबूत होने से उद्योग को फायदा होगा। रोहित अग्रवाल का मानना है कि मौजूदा मूल्यांकन पर श्री रेणुका और बलरामपुर चीनी मध्यावधि से दीर्घावधि के लिए अच्छे शेयर हैं। 26 रुपये और 51 रुपये के कीमत लक्ष्य को देखते हुए निवेशकों को गिरावट पर इन्हें खरीद लेना चाहिए। दूसरी तरफ विश्लेषक अधिक कर्ज की वजह से बजाज पर सकारात्मक नहीं दिख रहे हैं।

✓ N

Business Standard
16/12/13